No. 31924

INDIA
and
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Agreement for the promotion and protection of investments. Signed at London on 14 March 1994

Authentic texts: Hindi and English.

Registered by India on 19 June 1995.

INDE
et
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Accord relatif à la promotion et à la protection des investissements. Signé à Londres le 14 mars 1994

Textes authentiques : hindi et anglais.

Enregistré par l'Inde le 19 juin 1995.

[HINDI TEXT — TEXTE HINDI]

निवेशों के संवर्धन और संरक्षण

हेतु

ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

करार

ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है);

एक राज्य के निवेशकों द्वारा दूसरे राज्य के भू-भाग में अधिक निवेश को विकसित करने हेतु अनुकूल स्थितियां पैदा करने की इच्छा रखते हुए;

यह स्वीकारते हुए कि ऐसे निवेश संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत प्रोत्साहन और पारस्परिक संरक्षण व्यक्तिगत व्यापारिक पहल हेतु प्रेरण में सहायक होंगे और दोनों राज्यों में समृद्धि बढ़ेगी;

निम्नलिखित रूप में सहमत हुई है:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ :

(क) "कंपनियों" का अर्थ है:

(1) यूनाइटेड किंगडम के संबंध में: यूनाइटेड किंगडम के किसी भी भाग में अथवा ऐसे किसी भी भू-भाग में, जिस पर अनुच्छेद 13 के उपबंधों के अनुसार यह करार लागू होता है, प्रवृत्त कानून के तहत निगमित अथवा गठित निगम, फर्में और एसोसिएशनें;

(i) भारत के संबंध में: भारत के किसी भी भाग में प्रवृत्त कानून के तहत निगमित अथवा गठित निगम, फर्में और एसोसिएशनें ;

(ख) "निवेश" का अर्थ है स्थापित अथवा अधिगृहीत प्रत्येक किस्म की परिसम्पत्ति जिसमें संविदाकारी पक्ष जिसके भू-भाग में निवेश किए जा रहे हों, के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ऐसे निवेश के रूप में परिवर्तन शामिल हों और जिनमें विशेष रूप से, यद्यपि एकांतिक नहीं, निम्नलिखित शामिल हों:

(i) चल और अचल संपत्ति के साथ-साथ बंधक, ग्रहणाधिकारों अथवा धरोहर जैसे अन्य अधिकार;

(ii) कंपनी में शेयर और उसके स्टाक तथा डिबेंचर तथा कंपनी के हित के अन्य इसी प्रकार के रूप;

(iii) धन अथवा संविदा के तहत वित्तीय मूल्य युक्त किसी कार्य निष्पादन के अधिकारपूर्ण दावे;

(iv) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के संगत कानूनों के अनुसार बौद्धिक संपत्ति अधिकार, सदभाव, तकनीकी प्रक्रियाएं और जानकारी;

(v) कानून द्वारा अथवा संविदा के अन्तर्गत प्रदत्त व्यापारिक रियायतें जिनमें तेल और अन्य खनिजों की खोज करने तथा निकालने की रियायतें शामिल हैं ;

(ग) "निवेशकों" का अर्थ है संविदाकारी पक्ष का कोई राष्ट्रिक अथवा कंपनी;

(घ) "राष्ट्रिकों" का अर्थ है:

(i) यूनाइटेड किंगडम के संबंध में: यूनाइटेड किंगडम में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रिकों के रूप में अपनी स्थिति प्राप्त करने वाले वास्तविक व्यक्ति;

(ii) भारत के संबंध में: भारत में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में अपनी स्थिति प्राप्त करने वाले व्यक्ति;

(ङ) "आय" का अर्थ है निवेश द्वारा अर्जित मौद्रिक राशियां जैसे लाभ, ब्याज, पूंजीगत लाभ, लाभांश, रायल्टी और शुल्क;

§च§ "भू-भाग" का अर्थ है:

§1§ यूनाइटेट किंगडम के संबंध में: ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के सीमान्तर्गत जलक्षेत्र और सीमान्तर्गत जलक्षेत्र से आगे स्थित कोई भी समुद्री क्षेत्र जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में नामित हो अथवा भविष्य में नामित किया जाना हो जिसके भीतर यूनाइटेड किंगडम समुद्री तल और अवमृदा तथा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अधिकारों का प्रयोग कर सके, और ऐसा कोई भू-भाग जिस पर अनुच्छेद-13 के उपबंधों के अनुसार यह करार लागू होता हो;

§11§ भारत के संबंध में: भारत गणराज्य का भू-भाग जिसमें इसका सीमान्तर्गत जलक्षेत्र और इसका वायुक्षेत्र शामिल है तथा अन्य समुद्री क्षेत्र जिसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तल शामिल हैं जिसपर भारत गणराज्य का अपने प्रवृत्त कानूनों तथा समुद्र संबंधी कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता, प्रभुसत्तात्मक अधिकार अथवा अधिकारिता हो ।

अनुच्छेद 2

करार का कार्य-क्षेत्र

यह करार किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए सभी निवेशों, भले ही वे इस करार के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा बाद में किए गए हों, पर लागू होगा ।

अनुच्छेद 3

निवेश का संवर्धन और संरक्षण

§1§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के लिए अपने भू-भाग में निवेश करने तथा अपने कानूनों और नीति के अनुसार ऐसे निवेशों को स्वीकारने के लिए प्रोत्साहन देगा और अनुकूल स्थितियां पैदा करेगा ।

§2§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों के साथ सदैव उचित और समान व्यवहार किया जाएगा और उन्हें दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा मिलेगी ।

§3§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसा कोई भी वचन पूरा करेगा जो उसने दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों के संबंध में किया हो बशर्ते कि इस करार के अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत विवाद संबंधी संकल्प सामान्य स्थानीय न्यायिक समाधान के उपलब्ध न होने पर ही लागू होगा ।

अनुच्छेद 4

राष्ट्रीय व्यवहार और सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का व्यवहार

§1§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को, उन निवेशकों द्वारा उनके प्रचालन, प्रबन्ध, अनुरक्षण, प्रयोग, उपयोग अथवा निपटान सहित ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो इसके अपने निवेशकों के निवेशों अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों के निवेशों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

§2§ इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के साथ, उनके निवेशों पर अर्जित होने वाली आय के संबंध में सहित, ऐसा व्यवहार करेगा जो किसी तीसरे राज्य के निवेशकों को प्रदान किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

§3§ किसी भी संविदाकारी पक्ष अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों के साथ किए गए व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार प्रदान न करने के बारे में इस करार के उपबंधों का ऐसा अर्थ न लगाया जाए कि एक संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित से उभरने वाले किसी व्यवहार, प्राथमिकता अथवा विशेषाधिकार का लाभ दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को देने को बाध्य होगा:

§क§ कोई भी मौजूदा अथवा भावी सीमा-शुल्क संघ अथवा ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय करार जिसका कि कोई भी संविदाकारी पक्ष एक पक्ष हो अथवा बनने की संभावना हो; अथवा

§ख§ कराधान से पूर्णत: अथवा मुख्यत: संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय करार अथवा व्यवस्था या कराधान से पूर्णत: अथवा मुख्यत: संबंधित कोई देशीय विधान।

अनुच्छेद 5

स्वामित्वहरण

§1§ गैर-विभेदक आधार पर तथा उचित और समान क्षतिपूर्ति दिए जाने पर आर्थिक गतिविधि को विनियमित करने के लिए आन्तरिक अपेक्षाओं से संबंधित सार्वजनिक प्रयोजनों को छोड़कर, किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों का दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें ऐसे उपायों के अधीन नहीं लाया जाएगा जिनका प्रभाव राष्ट्रीयकरण अथवा स्वामित्वहरण §जिसे इसके बाद स्वामित्वहरण कहा गया है§ के समकक्ष हो । ऐसी क्षतिपूर्ति स्वामित्वहरण से एकदम पहले अथवा आसन्न स्वामित्वहरण के सार्वजनिक रूप से ज्ञात होने से पहले, जो भी पहले हो, स्वामित्वहरित निवेशों के प्रामाणिक मूल्य के बराबर हो, जिसमें भुगतान की तारीख तक उचित और समान दर पर ब्याज शामिल हो, बिना अनुचित विलम्ब के अदा की जाए, प्रभावी रूप से वसूल किए जाने योग्य हो और मुक्त रूप से अन्तरणीय हो ।

§2§ प्रभावित निवेशक को इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार स्वामित्वहरण करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानून के तहत उस पक्ष के न्यायिक अथवा किसी अन्य स्वतंत्र प्राधिकरण से अपने अथवा उसके मामले पर तथा अपने अथवा उसके निवेशों के मूल्य निर्धारण पर पुनर्विचार करवाने का अधिकार होगा ।स्वामित्वहरण करने वाला संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास करेगा कि ऐसा पुनर्विचार तत्काल किया जाए ।

§3§ जहां कोई संविदाकारी पक्ष किसी ऐसी कंपनी की परिसंपत्तियों का स्वामित्वहरण करता है जो इसके अपने भू-भाग के किसी भाग में प्रवृत्त कानून के अंतर्गत निगमित अथवा गठित की गई हो और जिसमें दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के शेयर हों, तब वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुच्छेद के पैरा §1§ के उपबंध दूसरे संविदाकारी पक्ष के ऐसे

निवेशकों, जो उन शेयरों के स्वामी है, के निवेशों के संबंध में तत्काल पर्याप्त और प्रभावी क्षतिपूर्ति की गारंटी देने हेतु यथासंभव लागू किए जाएं।

अनुच्छेद 6

हानियों की क्षतिपूर्ति

§1§ एक ऐसे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को जिसके दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए निवेशों को युद्ध अथवा अन्य सशस्त्र संघर्ष, राष्ट्रीय आपात स्थिति या दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सिविल उपद्रवों के कारण हानियां होती हैं तो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उसके लिए क्षतिपूर्ति, प्रत्यर्पण, मुआवजा या अन्य प्रकार से निपटान के संबंध में ऐसा अनुकूल व्यवहार किया जाएगा जो दूसरे संविदाकारी पक्ष को अपने निवेशकों को अथवा किसी तीसरे देश के निवेशकों को इन स्थितियों में किए गए व्यवहार से कम नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप होने वाले भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय होंगे।

§2§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को जिन्हें उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित किसी भी स्थिति में निम्नलिखित के कारण दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में हानियां उठानी पड़े;

§क§ दूसरे पक्ष की सेनाओं या अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण, अथवा

§ख§ दूसरे पक्ष की सेनाओं अथवा अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्तियों का विनाश, जो संघर्षपूर्ण कार्रवाई के कारण न हुआ हो अथवा स्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित न रहा हो,

तो उन्हें उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप होने वाली अदायगियां मुक्त रूप से परिवर्तनीय होंगी।

अनुच्छेद 7

निवेश और प्राप्तियों का प्रत्यावर्तन

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष निवेशों के मामले में दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को उनके निवेशों और प्राप्तियों के लिए अप्रतिबंधित अंतरण की अनुमति देगा । ये अंतरण उस परिवर्तनीय मुद्रा में जिसमें मूल रूप से पूंजी निवेश की गई थी अथवा निवेशक और संबद्ध संविदाकारी पक्ष द्वारा सहमत अन्य किसी परिवर्तनीय मुद्रा में अविलम्ब क्रियान्वित होंगे । जब तक निवेशक द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो, ये अंतरण प्रवृत्त मुद्रा विनिमय विनियमों के अनुसार अंतरण की तारीख को लागू विनिमय दर पर किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 8

प्रतिस्थापन

§1§ यदि एक संविदाकारी पक्ष अथवा इसकी निर्दिष्ट एजेंसी ने दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अपने किसी निवेशक द्वारा किए गए किसी प्रकार के निवेश के संबंध में गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के विरुद्ध किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/गारंटी दी हो और इस करार के अन्तर्गत उनके दावों के संबंध में ऐसे निवेशकों को भुगतान कर दिया हो तो दूसरा संविदाकारी पक्ष इस पर सहमत होगा कि पहला संविदाकारी पक्ष या इसके द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी प्रतिस्थापन के कारण उन निवेशकों के अधिकारों का प्रयोग करने और उनके दावों को प्रस्तुत करने की हकदार है । ये प्रतिस्थापित अधिकार या दावे ऐसे निवेशकों के मूल अधिकारों या दावों से अधिक नहीं होंगे ।

§2§ प्राप्त अधिकारों और दावों के अनुसरण में प्रथम संविदाकारी पक्ष द्वारा अपरिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त हुए किसी प्रकार के भुगतान प्रथम संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी भी प्रकार के किए गए सरकारी खर्चों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ निर्बाध उपलब्ध होंगे ।

अनुच्छेद 9

निवेशक तथा मेजबान सरकार के बीच विवाद का निपटान

§1§ एक संविदाकारी पक्ष के निवेशक तथा दूसरे संविदाकारी पक्ष के बीच इस करार के अन्तर्गत प्रथम संविदाकारी पक्ष के निवेश संबंधी किसी विवाद का निपटान, यथा संभव, विवादग्रस्त पक्षों के बीच बातचीत द्वारा शांतिपूर्वक किया जाएगा ।

§2§ ऐसा कोई विवाद जिसका दावे की लिखित अधिसूचना से छः माह की अवधि के अन्दर शांतिपूर्वक निपटान नहीं हुआ है तो उसे, यदि विवाद-ग्रस्त पक्ष सहमत हो जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के निपटारा नियमों के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए ।

§3§ जहां विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाता अथवा जहां इसे इस प्रकार भेजा जाता है परन्तु मध्यस्थता कार्यवाहियां निपटान करार के हस्ताक्षर करने से अन्यत्र प्रकार से समाप्त हो जाती हैं तो विवाद को विवाचन के लिए निम्न प्रकार भेजा जा सकता है:

§क§ यदि निवेशक का संविदाकारी पक्ष तथा दूसरा संविदाकारी पक्ष दोनों ही दूसरे राज्यों की सरकारों तथा राष्ट्रिकों के बीच निवेश विवाद निपटान अभिसमय, 1965 के पक्षकार हैं और निवेशक विवाद को लिखित रूप में निवेश विवाद के निपटान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को प्रस्तुत करने पर सहमत हो जाता है तो ऐसे विवाद को उक्त केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा; अथवा

§ख§ यदि विवादग्रस्त दोनों पक्ष निपटान, विवाचन अथवा तथ्यान्वेषण कार्य-वाही के संचालन संबंधी अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत इस प्रकार सहमत हो जाते हैं; अथवा

§ग§ विवाद से संबंधित दोनों में से किसी पक्ष द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, 1976 के विवाचन नियमों के अनुसार तदर्थ विवाचन न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है । ऐसी विवाचन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित लागू होगा;

(i) विवाचन न्यायाधिकरण में तीन विवाचक होंगे। प्रत्येक पक्ष एक विवाचक का चयन करेगा। ये दोनों विवाचक आपसी सहमति से एक तीसरा विवाचक अर्थात् अध्यक्ष नियुक्त करेंगे जो तीसरे राज्य का राष्ट्रिक होगा विवाचकों की नियुक्ति उस तारीख से दो माह के भीतर की जाएगी जब विवाद संबंधी एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस अनुच्छेद के पैरा (2) में पहले उल्लिखित छः माह की अवधि के अन्दर विवाद को विवाचन के लिए भेजने संबंधी अपनी मंशा के बारे में सूचित कर देगा;

(ii) यदि आवश्यक नियुक्तियाँ उप-पैरा (ग)(i) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर नहीं की जाती हैं, तो दोनों में से कोई भी पक्ष, कोई अन्य करार न होने पर, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष से आवश्यक नियुक्तियाँ करने का अनुरोध कर सकता है;

(iii) विवाचन पंचाट इस करार के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(iv) न्यायाधिकरण बहुमत से निर्णय लेगा;

(v) विवाचन न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा और दोनों पक्ष इसके पंचाट की सेवा शर्तों का अनुपालन करेंगे;

(i) विवाचन न्यायाधिकरण अपने निर्णय का आधार बताएगा और दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर कारण बताएगा;

(ii) प्रत्येक पक्ष अपने विवाचक तथा विवाचन कार्यवाहियों में अपने प्रतिनिधित्व के व्यय को वहन करेगा। अपने विवाचन कार्यों को करने के लिए हुए अध्यक्ष के व्यय तथा न्यायाधिकरण के शेष व्यय को दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। परन्तु न्यायाधिकरण अपने निर्णय में निदेश दे सकता है कि व्यय का अधिक भाग दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और वह पंचाट दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद 10

संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद

(1) संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार की व्याख्या अथवा प्रयोग से संबंधित विवादों को, जहाँ तक संभव हो, बातचीत के माध्यमसे निपटाया जाना चाहिए।

§2§ अगर संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद का निपटारा इस प्रकार विवाद उत्पन्न होने के समय से छः महीने के भीतर नहीं किया जा सकता तो यह दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर पंचाट न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा ।

§3§ ऐसा पंचाट न्यायाधिकरण प्रत्येक मामले के लिए निम्नानुसार तरीके से गठित किया जाएगा । पंचाट-निर्णय के लिए अनुरोध प्राप्ति के समय से दो महीनों के भीतर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष न्यायाधिकरण का एक सदस्य नियुक्त करेगा । वे दोनों सदस्य तब किसी तीसरे राष्ट्र के राष्ट्रिक का चयन करेंगे, जिसे दोनों संविदाकारी पक्षों के अनुमोदन पर न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । अध्यक्ष की नियुक्ति अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति की तारीख से दो महीनों के भीतर की जाएगी ।

§4§ अगर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक नियुक्तियाँ नहीं की जाती है तो दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी अन्य करार के न होते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियाँ करने के लिए आमंत्रित कर सकता है । अगर अध्यक्ष किसी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक हो अथवा उसे उक्त कार्य करने से अन्यथा रोका जाता है तो उपाध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियाँ करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । अगर उपाध्यक्ष दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक हो अथवा उसे भी उक्त कार्य करने से रोका जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगली वरिष्ठता वाले सदस्य, जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है, को आवश्यक नियुक्तियाँ करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

§5§ पंचाट न्यायाधिकरण बहुमत द्वारा अपना निर्णय करेगा । ऐसा निर्णय दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष न्यायाधिकरण के अपने सदस्य का और पंचाट कार्यवाहियों में उसके प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करेगा; अध्यक्ष का खर्च और अन्य शेष खर्च का वहन बराबर भाग में संविदाकारी पक्षों द्वारा किया जाएगा । तथापि, न्यायाधिकरण, अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि खर्च का बड़ा भाग दो संविदाकारी पक्षों में से किसी एक द्वारा वहन किया जाएगा और वह निर्णय दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा । न्यायाधिकरण अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा ।

अनुच्छेद 11

प्रयोज्य कानून

§1§ इस करार के उपबंधों के अधीन, समस्त निवेश संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, जिसमें इस प्रकार का निवेश किया जाता है, प्रवृत्त कानूनों द्वारा शासित होगा ।

§2§ इस अनुच्छेद के पैरा §1§ के होने पर भी, यह करार मेजबान संविदाकारी पक्ष को अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण हेतु कार्रवाई करने अथवा अत्यधिक आपात्तिक परिस्थितियों में भेदभाव रहित आधार पर सामान्यतया और उपयुक्त रूप से प्रयुक्त अपने कानूनों के अनुसार कार्रवाई करने के संबंध में प्रतिबाधित नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 12

अन्य नियमों की प्रयोज्यता

यदि वर्तमान में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष के उपबंध अथवा बाध्यताएं अथवा संविदाकारी पक्षों के बीच वर्तमान करार के अतिरिक्त इसके बाद स्थापित व्यवस्थाओं में ऐसे नियम, चाहे वे सामान्य हों अथवा विशिष्ट, अंतर्विष्ट हैं जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा निवेश के लिए वर्तमान करार द्वारा प्रदत्त व्यवहार से अधिक अनुकूल व्यवहार प्रदान करते हैं तो ऐसे नियम उस सीमा तक, जहां तक वे अधिक अनुकूल हैं, वर्तमान करार पर अभिभावी होंगे ।

अनुच्छेद 13

भू-भागीय विस्तार

इस करार के अनुसमर्थन के समय अथवा उसके बाद किसी भी समय, इस करार के उपबंधों का विस्तार ऐसे भू-भागों तक किया जा सकता है जिनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार उत्तरदायी है और जिस पर टिप्पणियों के आदान-प्रदान में संविदाकारी पक्षों के बीच सहमति हो ।

अनुच्छेद 14

करार का प्रवृत्त होना

यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा और अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

अनुच्छेद 15

करार की समयावधि और समाप्ति

यह करार दस वर्ष की समयावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा । उसके बाद यह उस तारीख से बारह महीने की समाप्ति तक प्रवृत्त रहेगा जिस तारीख को दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष ने दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने की लिखित सूचना दी हो । बशर्ते कि करार के प्रवृत्त रहते हुए किए गए निवेशों के संबंध में इसके उपबंध करार समाप्ति की तारीख के बाद पन्द्रह वर्षों की अवधि के लिए और उसके बाद भी सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुप्रयोग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के ऐसे निवेशों के संबंध में लागू रहेंगे ।

अनुच्छेद 16

करार का एक पाठ हिन्दी भाषा में होगा जो दोनों सरकारों द्वारा विधिवत्‌रूप से प्रमाणीकृत होगा और जो समान रूप से प्राधिकृत होगा ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से विधिवत् प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

आज दिनांक 14 मार्च, 1994 को लन्दन में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ ।

ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार की ओर से

भारत गणराज्य सरकार की ओर से

AGREEMENT[1] BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Desiring to create conditions favourable for fostering greater investment by investors of one State in the territory of the Other State;

Recognising that the encouragement and reciprocal protection under international agreement of such investment will be conducive to the stimulation of individual business initiative and will increase prosperity in both States;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

(a) "companies" means:

(i) in respect of the United Kingdom: corporations, firms and associations incorporated or constituted under the law in force in any part of the United Kingdom or in any territory to which this Agreement is extended in accordance with the provisions of Article 13;

(ii) in respect of India: corporations, firms and associations incorporated or constituted under the law in force in any part of India;

(b) "investment" means every kind of asset established or acquired, including changes in the form of such investment, in accordance with the national laws of the Contracting Party in whose territory the investment is made and in particular, though not exclusively, includes:

(i) movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, liens or pledges;

(ii) shares in and stock and debentures of a company and any other similar forms of interest in a company;

(iii) rightful claims to money or to any performance under contract having a financial value;

(iv) intellectual property rights, goodwill, technical processes and know-how in accordance with the relevant laws of the respective Contracting Party;

(v) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for and extract oil and other minerals;

[1] Came into force on 6 January 1995 by the exchange of the instruments of ratification, in accordance with article 14.

(c) "investors" means any national or company of a Contracting Party;

(d) "nationals" means:

(i) in respect of the United Kingdom: physical persons deriving their status as United Kingdom nationals from the law in force in the United Kingdom;

(ii) in respect of India: persons deriving their status as Indian nationals from the law in force in India;

(e) "returns" means the monetary amounts yielded by an investment such as profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees;

(f) "territory" means:

(i) in respect of the United Kingdom: Great Britain and Northern Ireland, including the territorial sea and any maritime area situated beyond the territorial sea of the United Kingdom which has been or might in the future be designated under the national law of the United Kingdom in accordance with international law as an area within which the United Kingdom may exercise rights with regard to the sea-bed and subsoil and the natural resources and any territory to which this Agreement is extended in accordance with the provisions of Article 13;

(ii) in respect of India: the territory of the Republic of India including its territorial waters and the airspace above it and other maritime zones including the Exclusive Economic Zone and continental shelf over which the Republic of India has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with its laws in force, and Public International Law including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.[1]

ARTICLE 2

Scope of the Agreement

This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, whether made before or after the coming into force of this Agreement.

ARTICLE 3

Promotion and Protection of Investment

(1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory, and admit such investments in accordance with its laws and policy.

(2) Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

[1] United Nations, *Treaty Series*, vols. 1833, 1834 and 1835, No. I-31363.

(3) Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party, provided that dispute resolution under Article 9 of this Agreement shall only be applicable to this paragraph in the absence of a normal local judicial remedy being available.

ARTICLE 4

National Treatment and Most-favoured-nation Treatment

(1) Each Contracting Party shall accord to investments of investors of the other Contracting Party, including their operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal by such investors, treatment which shall not be less favourable than that accorded either to investments of its own investors or to investments of investors of any third State.

(2) In addition each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party, including in respect of returns on their investments, treatment which shall not be less favourable than that accorded to investors of any third State.

(3) The provisions of this Agreement relative to the grant of treatment not less favourable than that accorded to the investors of either Contracting Party or of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:

(a) any existing or future customs union or similar international agreement to which either of the Contracting Parties is or may become a party, or

(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

ARTICLE 5

Expropriation

(1) Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose related to the internal requirements for regulating economic activity on a non-discriminatory basis and against fair and equitable compensation. Such compensation shall amount to the genuine value of the investment expropriated immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is the earlier, shall include interest at a fair and equitable rate until the date of payment, shall be made without unreasonable delay, be effectively realizable and be freely transferable.

(2) The investor affected shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to review, by a judicial or other independent authority of that Party, of his or its case and of the valuation of his or its investment in accordance with the principles set out in this paragraph. The Contracting Party making the expropriation shall make every endeavour to ensure that such review is carried out promptly.

(3) Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph (1) of this Article are applied to the extent necessary to guarantee prompt, adequate and effective compensation in respect of their investment to such investors of the other Contracting Party who are owners of those shares.

ARTICLE 6

Compensation for Losses

(1) Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency or civil disturbances in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. Resulting payments shall be freely transferable.

(2) Without prejudice to paragraph (1) of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the situations referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

(a) requisitioning of their property by its forces or authorities, or

(b) destruction of their property by its forces or authorities, which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded restitution or adequate compensation. Resulting payments shall be freely transferrable.

ARTICLE 7

Repatriation of Investment and Returns

Each Contracting Party shall in respect of investments grant to investors of the other Contracting Party the unrestricted transfer of their investments and returns. Transfers shall be effected without delay in the convertible currency in which the capital was originally invested or in any other convertible currency agreed by the investor and the Contracting Party concerned. Unless otherwise agreed by the investor transfers shall be made at the rate of exchange applicable on the date of transfer pursuant to the exchange regulations in force.

ARTICLE 8

Subrogation

(1) Where one Contracting Party or its designated agency has guaranteed any indemnity against non-commercial risks in respect of an investment by any of its investors in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investors in respect of their claims under this Agreement, the other Contracting Party agrees that the first Contracting Party or its designated agency is entitled by

virtue of subrogation to exercise the rights and assert the claims of those investors. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of such investors.

(2) Any payments received in non-convertible currency by the first Contracting Party in pursuance of the rights and claims acquired shall be freely available to the first Contracting Party for the purpose of meeting any official expenditure incurred in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 9

Settlement of Disputes between an Investor and a Host State

(1) Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in relation to an investment of the former under this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.

(2) Any dispute which has not been amicably settled within a period of six months from written notification of a claim may be submitted to international conciliation under the Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, if the parties to the dispute so agree.

(3) Where the dispute is not referred to international conciliation, or where it is so referred but conciliation proceedings are terminated other than by the signing of a settlement agreement, the dispute may be referred to arbitration as follows:

(a) if the Contracting Party of the investor and the other Contracting Party are both parties to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, 1965,[1] and the investor consents in writing to submit the dispute to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes such a dispute shall be referred to the Centre;
or

(b) if both parties to the dispute so agree under the Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings;
or

(c) to an *ad hoc* arbitral tribunal by either party to the dispute in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, 1976.[2] In respect of such arbitral proceedings, the following shall apply:

(i) The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators. Each party shall select an arbitrator. These two arbitrators shall appoint by mutual agreement a third arbitrator, the Chairman, who shall be a national of a third State. The arbitrators shall be appointed within two months from the date when one of the parties to the dispute informs the other of its intention to submit the dispute to arbitration within the period of the six months mentioned earlier in paragraph (2) of this Article;

[1] United Nations, *Treaty Series*, vol. 575, p. 159.
[2] *Ibid., Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17* (A/31/17), p. 34.

(ii) If the necessary appointments are not made within the period specified in sub-paragraph (c)(i), either party may, in the absence of any other agreement, request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments;

(iii) The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement;

(iv) The tribunal shall reach its decision by a majority of votes;

(v) The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding and the parties shall abide by and comply with the terms of its award;

(vi) The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party;

(vii) Each party concerned shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the abitral proceedings. The cost of the Chairman in discharging his arbitral function and the remaining costs of the tribunal shall be borne equally by the parties concerned. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two parties, and this award shall be binding on both parties.

ARTICLE 10

Disputes between the Contracting Parties

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through negotiation.

(2) If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six months from the time the dispute arose, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.

(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.

(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in

equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 11

Applicable Laws

(1) Subject to the provisions of this Agreement, all investment shall be governed by the laws in force in the territory of the Contracting Party in which such investments are made.

(2) Notwithstanding paragraph (1) of this Article nothing in this Agreement precludes the host Contracting Party from taking action for the protection of its essential security interests or in circumstances of extreme emergency in accordance with its laws normally and reasonably applied on a non-discriminatory basis.

ARTICLE 12

Application of other Rules

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such rules shall to the extent that they are more favourable prevail over the present Agreement.

ARTICLE 13

Territorial Extension

At the time of ratification of this Agreement, or at any time thereafter, the provisions of this Agreement may be extended to such territories for whose international relations the Government of the United Kingdom are responsible as may be agreed between the Contracting Parties in an Exchange of Notes.

ARTICLE 14

Entry into Force

This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date of exchange of Instruments of Ratification.

ARTICLE 15

Duration and Termination

This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter it shall continue in force until the expiration of twelve months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other. Provided that in respect of investments made whilst the Agreement is in force, its provisions shall

continue in effect with respect to such investments for a period of fifteen years after the date of termination and without prejudice to the application thereafter of the rules of general international law.

ARTICLE 16

There shall be a text of the Agreement in the Hindi language, duly certified by both Governments, which shall be equally authoritative.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at London this Fourteenth day of March 1994.

For the Government
of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:

DOUGLAS HURD

For the Government
of the Republic of India:

L. M. SINGHVI

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD[1] ENTRE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET L'INDE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République de l'Inde (ci-après dénommés les « Parties contractantes »),

Désireux de créer des conditions favorables à l'accroissement des investissements effectués par des investisseurs d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat;

Reconnaissant que l'encouragement et la protection desdits investissements en vertu d'un accord international contribueront à stimuler les initiative économiques individuelles et à augmenter la prospérité des deux Etats;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

a) Le terme « sociétés » désigne :

i) Dans le cas du Royaume-Uni, les entreprises et associations enregistrées ou établies en vertu de la législation en vigueur dans une partie quelconque du Royaume-Uni ou dans tout territoire auquel est étendu le champ d'application du présent Accord conformément aux dispositions de l'article 13;

ii) Dans le cas de l'Inde, les entreprises et associations enregistrées ou constituées aux termes de la législation en vigueur dans une partie quelconque de l'Inde;

b) Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature créés ou acquis, y compris les modifications à la forme dudit investissement, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué et il comprend notamment, mais non exclusivement :

i) Les biens meubles et immeubles et tous autres droits réels, tels qu'hypothèques, nantissements ou droits de gage;

ii) Les parts, actions et obligations d'une société et toutes autres formes d'intérêt dans une société;

iii) Les créances pécuniaires ou relatives à des prestations contractuelles dotées d'une valeur financière;

iv) Les droits de propriété intellectuelle, clientèle, procédés techniques et savoir-faire conformément à la législation pertinente de la Partie contractante intéressée;

[1] Entré en vigueur le 6 janvier 1995 par l'échange des instruments de ratification, conformément à l'article 14.

v) Les concessions commerciales octroyées aux termes de la loi ou d'un contrat, y compris les concessions portant sur la prospection et l'extraction de pétrole ou d'autres minerais;

c) Le terme « investisseurs » désigne les ressortissants ou les sociétés d'une Partie contractante;

d) Le terme « ressortissants » désigne :

i) Dans le cas du Royaume-Uni, les personnes physiques dont la condition de ressortissant du Royaume-Uni découle de la législation en vigueur au Royaume-Uni;

ii) Dans le cas de l'Inde, les personnes dont la condition de ressortissant découle de la législation en vigueur en Inde;

e) Le terme « revenus » désigue les produits monétaires, gains en capital, dividendes, redevances et honoraires;

f) Le terme « territoire » désigne :

i) Dans le cas du Royaume-Uni : la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord y compris la mer territoriale et toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale du Royaume-Uni qui a été ou pourrait dans l'avenir être désignée en vertu de la législation du Royaume-Uni conformément au droit international comme étant une zone sur laquelle le Royaume-Uni peut exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol et ressources naturelles, ainsi que tout territoire auquel est étendu le champ d'application du présent Accord conformément aux dispositions de l'article 13;

ii) Dans le cas de l'Inde : le territoire de la République de l'Inde, y compris la mer territoriale et l'espace aérien qui se trouve au-dessus ainsi que toute zone maritime, y compris la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la République de l'Inde possède des droits souverains de juridiction conformément à la législation en vigneur et le droit international public, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1992[1].

Article 2

PORTÉE DE L'ACCORD

Le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'ils aient été effectués avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 3

PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

1. Chaque Partie contractante encourage les investisseurs de l'autre Partie contractante à effectuer des investissements sur son territoire et crée des conditions favorables à cet effet; elle admet lesdits investissements conformément à sa législation et à ses principaux généraux.

[1] Nations Unies, *Recueil des Traités*, vols. 1833, 1834 et 1835, nº 1-31363.

2. Les investissements d'investisseurs de chaque Partie contractante bénéficient en tout temps d'un traitement juste et équitable ainsi que d'une protection et d'une sécurité totales sur le territoire de l'autre Partie contractante.

3. Chaque Partie contractante respecte toute obligation qu'elle aurait contractée s'agissant des investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, étant entendu que le règlement de différends aux termes de l'article 9 du présent Accord ne s'applique au présent paragraphe qu'à défaut de recours légaux normaux au niveau local.

Article 4

TRAITEMENT NATIONAL ET DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

1. Chaque Partie contractante accorde aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, y compris leur utilisation, gestion, entretien, exploitation, jouissance ou aliénation par lesdits investisseurs, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde soit aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements d'investisseurs de tout Etat tiers.

2. En outre, chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, y compris en ce qui concerne les revenus de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout Etat tiers.

3. Les dispositions du présent Accord concernant l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante ou à ceux d'un Etat tiers ne seront pas interprétées comme obligeant une Partie contractante à étendre aux investisseurs de l'autre Partie le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant :

a) D'une union douanière ou de tout accord international analogue existant ou futur auquel l'une ou l'autre Partie contractante est ou pourrait devenir partie; ou

b) De tout accord ou arrangement international portant en totalité ou principalement sur la fiscalité, ou de toute législation internationale portant en totalité ou principalement sur la fiscalité.

Article 5

EXPROPRIATION

1. Les investissements d'investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes ne sont ni nationalisés, ni expropriés, ni soumis à des mesures ayant un effet correspondant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommée « expropriation ») sur le territoire de l'autre Partie contractante si ce n'est pour une cause d'intérêt public portant sur des besoins internes relatifs à la réglementation de l'activité économique, sans discrimination et sous réserve d'une indemnisation suffisante et effective. Cette indemnisation est égale à la valeur réelle de l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation ou avant que l'expropriation imminente ne devienne de notoriété publique, la première de ces deux dates étant retenue; elle comprend les intérêts calculés à un taux juste et équitable jusqu'à la

date du paiement. L'indemnisation est versée sans délai injustifié, est effectivement réalisable et librement transférable.

2. L'investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la Partie contractante qui procède à l'expropriation, de faire examiner par une instance judiciaire ou autre instance indépendante de ladite Partie, son cas ainsi que l'évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent paragraphe. La Partie contractante qui a procédé à l'expropriation veille à assurer dans toute la mesure du possible que ledit examen soit effectué sans délai.

3. Lorsqu'une Partie contractante exproprie les avoirs d'une société enregistrée ou constituée en vertu de la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire et dont les investisseurs de l'autre Partie contractante détiennent des actions, elle veille à ce que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient appliquées dans la mesure voulue pour garantir le versement sans délai d'une indemnisation suffisante et effective aux investisseurs de l'autre Partie contractante détenteurs de ces actions, au titre de leur investissement.

Article 6

INDEMNISATION POUR PERTES

1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre conflit armé, d'un état d'urgence nationale ou d'émeutes sur le territoire de la dernière Partie contractante se voient accorder par cette dernière, en matière de restitution, de réparation, d'indemnisation ou autre mode de règlement, un traitement non moins favorable que celui que la dernière Partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers. Les sommes versées à ce titre sont librement transférables.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d'une des Parties contractantes qui, dans l'un des cas visés dans ledit paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante du fait :

a) De la réquisition de leurs biens par ses forces ou autorités; ou

b) De la destruction de leurs biens par ses forces ou autorités, qui ne résulterait pas de combats ou n'aurait pas été exigée par la situation,

se verront accorder leur restitution ou une indemnisation suffisante. Les sommes versées à ce titre sont librement transférables.

Article 7

RAPATRIEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DES REVENUS

En ce qui concerne les investissements, chaque Partie contractante reconnaît aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de leurs investissements et revenus. Les transferts sont effectués sans délai dans la monnaie convertible dans laquelle les capitaux ont initialement été investis ou toute autre monnaie convertible dont conviendraient l'investisseur et la Partie contractante concernée. A moins que l'investisseur n'en convienne autrement, les transferts se font au taux de

change en vigueur à la date du transfert conformément aux règlements de change en vigueur.

Article 8

SUBROGATION

1. Lorsque l'une des Parties contractantes ou l'organisme qu'elle aura désigné a accordé une garantie d'indemnisation contre des risques de nature non commerciale s'agissant d'un investissement effectué par l'un quelconque de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante et a effectué un paiement audit investisseur au titre de ses réclamations en vertu du présent Accord, l'autre Partie contractante a le droit de faire valoir par subrogation les droits et les réclamations du dit investisseur.

2. La première Partie contractante dispose librement de tous les paiements qu'elle a reçus en monnaie non convertible au titre des droits et créances acquis, aux fins de couvrir ses dépenses officielles encourues sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 9

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET UN PAYS HÔTE DE L'INVESTISSEMENT

1. Tout différend entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante relatif à un investissement dudit investisseur effectué aux termes du présent Accord, est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable au moyen de négociation entre les parties au différend.

2. Tout différend qui ne peut être réglé à l'amiable dans un délai de six mois suivant une notification écrite d'une réclamation est soumis à une procédure de conciliation en vertu des Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, sous réserve que les Parties contractantes en soient d'accord.

3. Lorsque le différend n'est pas soumis à une procédure de conciliation internationale ou lorsqu'il y est soumis et qu'il est mis fin à la procédure sans qu'elle ait abouti à la signature d'un accord de règlement, le différend peut être soumis à arbitrage de la manière suivante :

a) Si la Partie contractante de l'investisseur et l'autre Partie contractante sont toutes deux parties à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats de 1965[1], et si l'investisseur concerné consent par écrit à soumettre le différend au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, ledit différend est alors soumis audit Centre;

b) Si les deux parties au différend en sont d'accord, le Mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédure de conciliation, d'arbitrage ou de constatation des faits;

[1] Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 575, p. 159.

c) A un tribunal d'arbitrage constitué pour la circonstance, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend conformément aux Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, 1976[1]. S'agissant des procédures d'arbitrage, les arrangements suivants s'appliquent :

i) Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Chaque Partie désigne un arbitre. Ceux-ci désignent par accord mutuel un troisième arbitre qui assure la présidence et qui est un ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des parties au différend aura informé l'autre partie de son intention de soumettre le différend à arbitrage dans le délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article;

ii) Si les désignations nécessaires n'ont pas été effectuées dans les limites du délai imposé à l'alinéa *c* sous-alinéa i, l'une ou l'autre des parties peut, à défaut de tout autre accord, prier le Président de la Cour internationale de Justice de procéder auxdites désignations;

iii) La décision arbitrale est prise conformément aux dispositions du présent Accord;

iv) La décision du tribunal est prise à la majorité des voix;

v) La décision au Tribunal est obligatoire et a force exécutoire et les parties doivent s'y conformer et procéder à son exécution;

vi) Le tribunal arbitral justifie sa décision et explique les raisons qui la sous-tendent, à la demande de l'une ou l'autre des parties;

vii) Chaque partie intéressée assume les frais de son arbitre et de sa représentation aux procédures arbitrales. Les frais relatifs au Président dans l'exercice de ses fonctions et les autres frais relatifs au tribunal sont partagés également entre les parties intéressées. Toutefois, il est loisible au tribunal de stipuler dans sa décision qu'une proportion plus importante des frais sera assumée par l'une des deux parties et une telle décision lie les deux parties.

Article 10

DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord doit, si possible, être réglé par voie de négociation.

2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé de cette manière dans un délai de six mois suivant l'apparition de celui-ci, il est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

3. Le tribunal arbitral est constitué dans chaque cas de la manière suivante : dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante désigne un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d'un Etat tiers qui, après approbation des Parties contractantes, est nommé président du tribunal. La nomination du président intervient dans un délai de deux mois à compter de la nomination des deux autres membres.

[1] Nations Unies, *Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-et-unième session, Supplément n° 17* (A/31/17), p. 36.

4. Si dans les délais stipulés au paragraphe 3 du présent article, les nominations nécessaires n'ont pas été effectuées, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, à défaut de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est empêché de toute autre manière de s'acquitter de cette tâche, le Vice-Président est prié de procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est lui aussi empêché de s'acquitter de cette tâche, il est demandé au membre de la Cour internationale de Justice de rang immédiatement inférieur qui ne soit pas ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes de procéder aux nominations nécessaires.

5. Le tribunal arbitral se prononce à la majorité. Ses décisions ont force exécutoire pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante assume les frais du membre du tribunal qu'elle a désigné et de ses représentants à la procédure arbitrale. Les frais du président et les autres frais sont répartis à égalité entre les Parties contractantes. Le tribunal peut toutefois, dans sa décision, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit à la charge d'une des deux Parties contractantes et cette décision a force exécutoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal arrête lui-même sa procédure.

Article 11

LOIS APPLICABLES

1. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les investissements sont régis par les lois en vigueur sur le territoire de la Partie contractante sur lequel ils sont effectués.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucune disposition du présent Accord ne fait obstacle à ce que la Partie contractante d'accueil prenne des mesures propres à assurer ses intérêts essentiels s'agissant de la sécurité ou à l'occasion de situations d'extrême urgence conformément à sa législation normalement et raisonnablement appliquée sur une base non discriminatoire.

Article 12

APPLICATIONS D'AUTRES RÈGLES

Si les dispositions de la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou encore ses obligations en vertu du droit international existantes ou instituées par la suite entre les Parties contractantes en sus du présent Accord contiennent des règles, générales ou particulières, accordant aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, lesdites règles, dans la mesure où elle sont plus favorables, prévaudront sur les dispositions du présent Accord.

Article 13

EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

A la date de la ratification du présent Accord, ou à toute date ultérieure, l'application de ses dispositions pourra être étendue aux territoires dont le Gouvernement

du Royaume-Uni assume les relations internationales, si les Parties contractantes en conviennent par échange de notes.

Article 14

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Article 15

DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent Traité demeurera en vigueur pendant une période de 10 ans. Il sera par la suite reconduit jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l'une ou l'autre des Parties contractantes aura notifié par écrit à l'autre Partie son intention de le dénoncer. Toutefois, en ce qui concerne les investissements effectués au cours de sa validité, ses dispositions continueront à s'appliquer pendant une période de 20 ans suivant la date de son expiration et sans préjudice de l'application ultérieure des règles générales du droit international.

Article 16

Il existera un texte hindi de l'Accord, dûment certifié conforme par les deux gouvernements, qui fera également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussigués, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Londres, le 14 mars 1994.

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :

DOUGLAS HURD

Pour le Gouvernement
de la République de l'Inde :

L. M. SINGHVI